☎: General: 0471- 2312910, 2318153, 2318154, 2318155 Chairman: 2318150 Member Secretary: 2318151
e-mail: chn.kspcb@gov.in; ms.kspcb@gov.in FAX: 2318152 web: kspcb.kerala.gov.in

KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD

കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

Pattom P.O., Thiruvananthapuram – 695 004

പട്ടം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695 004

KSPCB/98/2024-SEE-1 Date: 05/02/2024

CIRCULAR

Sub: - Commencement of Validity of Environmental Clearance for Mining & quarrying projects- reg.

Ref: - 1. MoEF&CC notification no. S.O. 1533(E) dated 14/09/2016.
2. MoEF&CC notification no. S.O. 1807(E) dated 12/04/2022.
3. G.O No. 1257/2023/ID dated 14/12/2023,
4. Order dated 17/01/2024 in WP(C) No.1548 of 2024 of the Hon'ble High, Court of Kerala.

The Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC) vide reference cited 2nd has made amendments to notification cited 1st regarding the validity of Environmental Clearance (EC) for projects. As per this notification,

"(i) in paragraph 9,-

(a) for sub paragraphs (i) and (ii), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

(i) The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior Environmental Clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub-paragraph

(iii) of paragraph 8, to the start of production operations by the project or activity; or completion of all construction operations in case of construction projects relating to item 8 of the Schedule, to which the application for prior environmental clearance refers:

Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease."

Based on the MoEF &CC notification cited 2nd, the Government of Kerala had issued G.O. cited 3rd clarifying that the validity of Environmental Clearance for the mining lease issued by the Department of Mining & Geology shall commence from the date of execution of the mining lease/permit.

The Hon'ble High Court of Kerala had also clarified vide the Order cited (4) in WP(C) No.1848 of 2024 that Board shall pass orders on the request of the petitioner for extension of consent validity in the light of the Government order cited 3rd. Based on the above, application for Consent to operate and Renewal of Consent to operate of quarries, the validity of EC shall be taken in such a way that it shall commence from the date of execution of mining lease/permit.

CHAIRPERSON

To

1. The Chief Environmental Engineer,
   Head Office, Thiruvananthapuram
   Regional Office, Thiruvananthapuram /Ernakulam/Kozhikode.
2. The Senior Environmental Engineer,
   District Office. Kottayam
3. The Environmental Engineer, District Office,
   Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alapuzha, Idukki,
   Ernakulam-1, Ernakulam-2, Environmental Surveillance Centre Eloor.Thrissur,
   Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Kannur, Wayanad, Kasargod.

Copy to:-

1) All Technical Staff in HO
2) IT Cell (for uploading in the website)
3) C.A. to CHN & MS

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2244] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938
No. 2244] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

का.आ. 2944(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के पश्चात् तत्कालीन भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पर्यावरणीय अनापत्ति(ईसी) की विधिमान्यता से संबंधित पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9. पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) की विधिमान्यता:

(i) "पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता से वह अवधि अभिप्रेत है जिससे विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की जाती है या आवेदक द्वारा यह समझा जा सकेगा कि यह ऊपर पैरा 8 के उप पैरा (iii) के अधीन परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन आरंभ करने या संनिर्माण परियोजना की दशा में (अनुसूची की मद 8) सभी संनिर्माण प्रचालन पूरा करने, जिसके लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन का निर्देश करता है, मंजूर की गई है। किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं (अनूसूची की मद 1(ग) की दशा में, दस वर्ष की अवधि के लिए, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन

समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के लिए और सभी अन्य परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों की दशा में सात वर्ष होगी ।

(ii) क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरों की दशा में (मद 8(ख) सात वर्ष की विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगी जो विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व हो:

परंतु उपरोक्त पैरा (i) और पैरा (ii) के संबंध में विधिमान्यता की इस अवधि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, यदि कोई आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर आवेदन किया जाता है:

परंतु यह और कि विनियामक प्राधिकरण यथास्थिति, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति से, ऐसा विस्तार मंजूर करने के लिए परामर्श कर सकेगा ।

(iii) जहां उपरोक्त उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन विस्तार के लिए आवेदन-

(क) पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीस दिन के भीतर फाइल किया गया है वहां ऐसे मामले संबद्ध विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के निर्दिष्ट किए जाएंगे और उनकी सिफारिशों के आधार पर, विलंब, यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या सदस्य सचिव, जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के सूतर पर माफ किया जा सकेगा ;
(ख) जब पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीस दिन से अधिक किंतु ऐसी विधिमान्य अवधि के पश्चात् नब्बे दिन से कम के भीतर फाइल किया गया है तब विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला सूतरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर विलंब, यथास्थिति पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री या अध्यक्ष के अनुमोदन से माफ किया जा सकेगा:

परंतु विलंब के लिए कोई माफी पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् नब्बे दिन से परे फाइल किए गए विस्तार संबंधी किसी आवेदन के लिए मंजूर नहीं की जाएगी ।"

[फा. सं. 22-27/2015-आईए- III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013, का.आ., 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ., 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ., 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1559(अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252(अ),

तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015, का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015, का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015, का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015, का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 और का.आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 th September, 2016

S.O. 2944(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment(Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of rule 5 of the said rule, in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 namely:-

In the said notification, for paragraph, 9 relating to Validity to Environment Clearance (EC), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"**9.Validity of Environmental Clearance (EC):**

(i) The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub-paragraph (iii) of paragraph 8, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects [item 1(c) of the Schedule], project life as estimated by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and seven years in the case of all other projects and activities.

(ii) In the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period of seven years shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer:

Provided that this period of validity with respect to sub-paragraphs (i) and (ii) above may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of three years if an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form I, and Supplementary Form IA, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule):

Provided further that the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, for grant of such extension.

(iii) Where the application for extension under sub-paragraphs (i) and (ii) above has been filed-

(a) within thirty days after the validity period of Environmental Clearance, such cases shall be referred to concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee and based on their recommendations, the delay shall be condoned at the level of the Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee or Member Secretary, District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be;

(b) more than thirty days after the validity period of Environmental Clearance but less than ninety days after such validity period, then, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, the delay shall be condoned with the approval of the Minister in charge of Environment, Forest and Climate Change or Chairman, as the case may be :

Provided that no condonation for delay shall be granted for any application for extension filed beyond ninety days after the validity period of Environmental Clearance.".

[F. No. 22-27/2015-IA-III]
MANOJ KUMAR SINGH, Jt Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2204(E) dated the 19th July, 2013, S.O.2555(E) dated the 21st August, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014, S.O. 2600 (E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O.1834 (E) dated the 6th July, 2015, S.O.2571 (E) dated the 31st August, 2015, S.O.2572 (E) dated the 14th September, 2015, S.O.141 (E) dated the 15th January, 2016 and S.O.648 (E) dated the 3rd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.17 11:41:07 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235092
CG-DL-E-13042022-235092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1720] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944
No. 1720] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1807(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा 2 के खंड (v) और उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में, परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए, संख्यांक का.आ. 1553(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित किया है;

और, पूर्व अनुभवों के आधार पर, यह उल्लेखनीय है कि नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं और जल शक्ति परियोजनाओं को पूरा होने की अवधि विभिन्न मुद्दों जैसे भौगोलिक आश्चर्य, वन मंजूरी में देरी, भूमि अर्जन, स्थानीय मुद्दों, पुनर्वास और पुनःव्यवस्थापन आदि के कारण परियोजना पूरी होने में अधिक समय लगता है, जो प्रायः परियोजना प्रस्तावक के नियंत्रण से बाहर होता है और इस संदर्भ में, केन्द्रीय सरकार को ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वैधता बढ़ाना आवश्यक हो जाता है;

और, अन्य परियोजनाएं भी, ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों सहित स्थानीय मामलों को संबोधित करने के लिए लगे समय पर विचार करने के लिए, केन्द्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे ऐसे पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता की सीमा को बढ़ा सकती है

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम 2015, के प्रारंभ की तारीख से ही, सभी खनिज पट्टे पचास वर्षों की अवधि के लिए दिए जा रहे हैं, और तद्नुसार, केन्द्रीय सरकार खनन के पर्यावरण मंजूरी की वैधता को, संरेखित करना

आवश्यक समझती है जो वर्तमान में उपयुक्त पर्यावरणी सुरक्षा और पुनर्विलोकन के अधीन अधिकतम तीस वर्षों की अवधि तक अनुज्ञेय है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 को नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा की अभिमुक्ति के पश्चात् भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का और संशोधन संख्याकं का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा करती है, अर्थात् :-

(i) पैरा 9 में,

(क) उपपैरा (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) "पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी विनियामक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है, या आवेदक द्वारा पैरा 8 के उपपैरा (iii) के अधीन स्वीकृत किया गया माना जा सकता है, की सुरुवात परियोजना या गतिविधियों द्वारा उत्पादन प्रचालन ; या अनुसूची के मद 8 से संबंधित निर्माण परियोजनाओं के मामले में सभी निर्माण प्रचालनों को पूरा करना है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन संदर्भित है :

परंतु खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामलें में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे ।

(ii) किसी विद्यमान या नई परियोजना या क्रियाकलाप के लिए दी गई पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी उस अवधि के लिए वैध होगी,जो-

(क) नदी घाटी परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में तेरह वर्ष [अनुसूची का मद 1(ग)]; (ख) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं या क्रियाकलापों और परमाणु ईंधन के प्रसंस्करण के मामले में पंद्रह वर्ष [अनुसूची का मद 1(ङ)];

(ग) खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट खनन परियोजनाओं और नदी घाटी परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के सिवाए अन्य सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों के मामले में दस वर्ष।

(iii) क्षेत्र विकास परियोजनाओं और टाउनशिप [मद 8(ख)] के मामले में, दस वर्ष की वैधता अवधि केवल ऐसी क्रियाकलापों तक सीमित होगी जो विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व हो सकता है:

परंतु यह कि इस उप-पैरा और उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध परियोजनाओं और क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि को नदी घाटी परियोजनाओं के मामले में, संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा वैध पर्यावरण मंजूरी के संबंध में अधिकतम दो वर्ष की अवधि द्वारा, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और परमाणु ईंधन के प्रसंस्करण के मामले में पांच वर्ष और अन्य सभी परियोजनाओं के मामले में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि आवेदन विद्यमान पर्यावरण मंजूरी की वैधता अवधि के भीतर आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण के लिए अधिकथित प्रोफार्मा में किया जाता है:

परंतु यह और कि विनियामक प्राधिकरण ऐसे विस्तार के अनुदान से पहले संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से भी परामर्श कर सकता है।

(iv) खनन परियोजनाओं के लिए दी गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी, समय-समय पर, अधिकतम तीस वर्ष, जो भी पहले हो, के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और नवीनीकृत खनन योजना में निर्धारित परियोजना जीवन के लिए मान्य होगी:

परंतु इस उप-पैरा में सम्मिलित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि को अगले बीस वर्षों के लिए, तीस वर्षों से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि विद्यमान पर्यावरण मंजूरी में अधिकथित विद्यमान पर्यावरण सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता की जांच,तीस वर्ष की पर्यावरणीय मंजूरी की अधिकतम वैधता अवधि के भीतर परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन

समिति द्वारा हर पांच वर्ष बाद और तत्पश्चात विस्तारित पर्यावरण मंजूरी, जैसा आवश्यक समझा जाए, परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त होने पर पर्यावरण प्रबंधन योजना में ऐसे अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए हर पांच वर्ष में, खनन पट्टे की वैधता या खनन जीवन की समाप्ति या पचास वर्ष, जो भी पहले हो, तक की जाएगी।";

(ख) "(iii) जहां उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन विस्तार के लिए आवेदन फाइल किया गया है" कोष्ठक, अंक और शब्दों के लिए, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(v) जहां उप-पैरा (ii), (iii) और (iv) के अधीन विस्तार के लिए आवेदन अधिकथित प्रोफार्मा में फाइल किया गया है"।

[फा. सं. आईए 3-22/10/2022-आईए.III]

तन्मय कुमार, अपर सचिव,

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2859(अ), तारीख 16 जुलाई, 2021 के अधीन अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1807(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

And whereas, based on the past experiences, it is noted that Nuclear Power Projects and Hydro Power Projects have high gestation period due to various issues such as geological surprises, delay in Forest Clearance, land acquisition, local issues, rehabilitation and resettlement, etc., which are often beyond the control of project proponent and in this context, the Central Government deems it necessary to extend the validity of Environmental Clearance (EC) for such projects;

And whereas, for other projects also, considering the time taken for addressing local concerns including environmental issues related to the implementation of such projects, the Central Government deems it necessary to extend the validity of such ECs;

And whereas, as per the provisions of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), on and from the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, all mining leases are being granted for a period of fifty years, and accordingly, the Central Government deems it necessary to align the validity of mining ECs which is currently permissible up to a maximum duration of thirty years, subject to review and appropriate environmental safeguards;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 9,-

(a) for sub paragraphs (i) and (ii), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

(i) The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior Environmental Clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub-paragraph (iii) of paragraph 8, to the start of production operations by the project or activity; or completion of all construction

operations in case of construction projects relating to item 8 of the Schedule, to which the application for prior environmental clearance refers:

Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease.

(ii) The prior environmental clearance granted for an existing or new project or activity shall be valid for a period of,-

(a) thirteen years in the case of River Valley projects or activities [item 1(c) of the Schedule];

(b) fifteen years in the case of Nuclear power projects or activities and processing of nuclear fuel [item 1(e) of the Schedule];

(c) ten years in the case of all other projects and activities other than the Mining projects and River Valley Projects and Nuclear power projects referred to in clauses (a) and (b).

(iii) In the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period of ten years shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer:

Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to the Projects and Activities listed in this sub- paragraph and sub-paragraphs (ii) may be extended in respect of valid Environmental Clearance, by the regulatory authority concerned by a maximum period of two years in the case of River Valley projects, five years in the case of Nuclear power projects and processing of nuclear fuel and one year in the case of all other projects, if an application is made in the laid down proforma to the regulatory authority by the applicant within the validity period of the existing Environment Clearance:

Provided further that the regulatory authority may also consult the concerned Expert Appraisal Committee before grant of such extension.

(iv) The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier:

Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to projects or activities included in this sub-paragraph may be extended by another twenty years, beyond thirty years, subject to the condition that the adequacy of the existing environmental safeguards laid down in the existing Environmental Clearance shall be examined by concerned Expert Appraisal Committee every five years beyond thirty years, on receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the maximum validity period of Environmental Clearance of thirty years, and subsequently on receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the validity period of the extended Environment Clearance, every five years for incorporating such additional environment safeguards in the Environmental Management Plan , as may be deemed necessary, till the validity of the mining lease or end of life of mine or fifty years, whichever is earlier.";

(b) for the brackets, figures and words "(iii) Where the application for extension under sub-paragraphs (i) and (ii) has been filed", the following shall be substituted, namely:-

"(v) Where the application for extension under sub-paragraphs (ii), (iii) and (iv) has been filed in the laid down proforma".

[F. No. IA3-22/10/2022-IA.III]

TANMAY KUMAR, Add. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended, vide the notification number S.O. 2859(E), dated the 16th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.13 12:19:12 +05'30'

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1257/2023/ID

"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"

കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

വ്യവസായ വകുപ്പ്- മൈനിംഗ് & ജിയോളജി- ലീസുകളുടെയും, പെർമിറ്റുകളുടെയും പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയുടെ കാലാവധി ആരംഭിക്കുന്നത് ലീസ് എക്സ്ടിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതലും പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കുന്ന തീയതി മുതലും ആയിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്ത വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

വ്യവസായ (എ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1257/2023/ID തീയതി,തിരുവനന്തപുരം, 14-12-2023

പരാമർശം:-

1. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 14.09.2016 ലെ S.O1533(E) നമ്പർ വിജ്ഞാപനം.
2. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 12.04.2022 ലെ S.O. 1807(E) നമ്പർ വിജ്ഞാപനം.
3. ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 20.12.2022 ലെ WP(C) No.35855/2022, WP(C) No.35871/2022 കേസുകളിലെ വിധിന്യായം.
4. കാറി EC ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ആക്കാവിള സതീക്ക് 21.08.2023 ൽ സമർപ്പിച്ച നിവേദനം.
5. മൈനിംഗ് & ജിയോളജി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 20.09.2023 ലെ DMG/2652/2023-M5 നമ്പർ കത്ത്.

ഉത്തരവ്

മൈനിംഗ് ലീസ് അനുവദിക്കുന്ന തീയതി മുതലാണ് പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയുടെ കാലാവധി തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് സൂചന(2) പ്രകാരം കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചന(3) പ്രകാരമുള്ള ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളിൽ സ്പഷ്ടീകരണം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ആയതിനാൽ മൈനിംഗ് & ജിയോളജി വകുപ്പ് നൽകുന്ന ലീസുകളിലെ പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയുടെ കാലാവധി മൈനിംഗ് ലീസ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആക്കി വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കണമെന്ന് സൂചന(4) പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

2. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സൂചന (1) പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൽ 12.04.2022 ലെ S.O. 1807(E) നമ്പർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ പാരിസ്ഥിതികാനുമതി സംബന്ധിച്ച് ഖണ്ഡിക (9) താഴെപറയുംപ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

(i) in paragraph 9,-

(a) for sub paragraphs (i) and (ii), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

(i) The "Validity of Environment Clearance" is meant the period from which a prior Environmental Clearance is granted by the regulatory authority, or may

be presumed by the applicant to have been granted under sub-paragraph (iii) of paragraph 8, to the start of production operations by the project or activity; or completion of all construction operations in case of construction projects relating to item 8 of the Schedule, to which the application for prior environmental clearance refers:

Provided that in the case of mining projects or activities the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease.

3. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 12.04.2022 ലെ S.O. 1807(E) നമ്പർ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൈനിംഗ് & ജിയോളജി വകുപ്പ് നൽകുന്ന ലീസിനെ്റ പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയുടെ കാലാവധി ആരംഭിക്കുന്നത് ലീസ് എക്സ്ടിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്ത വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

(ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)
എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ, മൈനിംഗ് & ജിയോളജി വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
എല്ലാ ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റുമാർക്കും
പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ്
ശ്രീ. ആക്കാവിള സതീക്ക്, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ക്വാറി EC ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, TC 67/1114/1, ഭാരത് പെട്രാൾ പമ്പ്, പരവൻകുന്ന്, മണക്കാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ആഡിറ്റ്) കേരള, തിരുവനന്തപുരം.
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (എ & ഇ) കേരള, തിരുവനന്തപുരം.
വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക (വെബ് & ന്യൂ മീഡിയ) വകുപ്പ്.
സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ/ ഓഫീസ് കോപ്പി.

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം
Signed by
Sachin V R
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ
Date: 16-12-2023 12:04:14

IN THE HIGH COURT OF KERALA AT ERNAKULAM

PRESENT

THE HONOURABLE MR.JUSTICE VIJU ABRAHAM

Wednesday, the 17th day of January 2024 / 27th Pousha, 1945

WP(C) NO. 1848 OF 2024

PETITIONER:

M/S. MALABAR GRANITE INDUSTRIES, REPRESENTED BY ITS MANAGING PARTNER, KHADEEJA M.K., AGED 59 YEARS, D/O. ALAVI HAJI, THONNIPARAMBIL HOUSE, PERUVALLOOR PO, MALAPPURAM, PIN-673638

RESPONDENTS:

1. **THE DISTRICT GEOLOGIST, MALAPPURAM DISTRICT, MINING AND GEOLOGY DEPARTMENT, OFFICE OF THE DISTRICT GEOLOGIST, MINI CIVIL STATION, MANJERI, MALAPPURAM, PIN-676121**
2. **THE DIRECTOR ,MINING AND GEOLOGY DIRECTORATE, KESAVADASAPURAM, PATTOM PALACE PO, THIRUVANANTHAPURAM, PIN-695004**
3. **STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (SEIAA KERALA), REPRESENTED BY ITS MEMBER SECRETARY, 4 TH FLOOR, KSRTC BUS TERMINAL COMPLEX, THIRUVANANTHAPURAM, PIN-695001**
4. **MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, PARYAVARAN BHAVAN, NEW DELHI, REPRESENTED BY ITS DIRECTOR, PIN-110014**
5. **THE KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD, REPRESENTED BY ITS CHAIRMAN, HEAD OFFICE, PATTOM P.O, THIRUVANANTHAPURAM, PIN-695004**

Writ Petition (Civil) praying inter alia that in the circumstances stated in the affidavit filed along with the WP(C) the High Court be pleased to pass an interim order directing the 5 th respondent to renew Ext. P4 upto 19/3/2025 in the light of covid extension and Ext. P10 go 1257/2023 forthwith, pending disposal of this writ petition.

This petition coming on for orders upon perusing the petition and the affidavit filed in support of WP(C) and upon hearing the arguments of M/S. T.P.SAJID, SHIFA LATHEEF, MUHAMMED HAROON A.N., HASHARURAHIMAN U. & MOHEMED FAVAS, Advocates for the petitioner, the court passed the following:

VIJU ABRAHAM, J.

W.P.(C) No.1848 of 2024

Dated this the 17th day of January, 2024

ORDER

Admit.

2. The learned Govt. Pleader takes notice for respondents 1 and 2. Respective Standing Counsel takes notice for respondents 3 and 5. The learned DSG takes notice for the 4th respondent.

3. The petitioner seeks for a direction to the 5th respondent to consider and pass orders on Ext.P11 application for renewal of consent to operate. The petitioner submits that going by Ext.P10 Government Order, the lease period is till 19.03.2025.

After hearing both sides, there will be a direction to the 5th respondent to take up Ext.P11 and pass orders on the same in the light of Ext.P10 Government Order.

Sd/-
VIJU ABRAHAM
JUDGE

sm/

APPENDIX OF WP(C) 1848/2024

Exhibit P4	**TRUE COPY OF THE RELEVANT PAGES OF THE CONSENT TO OPERATE DATED 4/10/2018 ISSUED BY THE KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD TO THE PETITIONER**
Exhibit P10	**TRUE COPY OF THE GO NO. 1257/2023 /ID DATED 14/12/2023 ISSUED BY THE INDUSTRIAL DEPARTMENT , GOVERNMENT OF KERALA**

THE HIGH COURT OF KERALA
सत्यमेव जयते